



Daily करेंट अफेयर्स

» 27 जून 2025



NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. NeGD और IIT दिल्ली ने सरकारी अधिकारियों के लिए शासन में AI पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया।



26-27 जून 2025 को, MeitY के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने IIT दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग में 'गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा वितरण में जिम्मेदारी से AI का उपयोग करने के लिए सुसज्जित किया गया।

- AI प्रशिक्षण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की क्षमता निर्माण योजना (CB चरण III) के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी स्तरों पर डिजिटल शासन में संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों तरह की दक्षताओं का विकास करना है।

- कार्यक्रम का उद्घाटन रजनीश कुमार (COO और निदेशक, NeGD), सुनील शर्मा (निदेशक, NeGD) और प्रोफेसर सूर्य प्रकाश सिंह, DMS के प्रमुख, IIT दिल्ली ने किया - जो सरकार और शिक्षा जगत के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है।

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और स्वायत्त निकायों के 59 सरकारी अधिकारियों के एक समूह ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला में नीति-निर्माताओं, प्रबंधकों और तकनीकी प्रमुखों को लक्षित किया गया, जो अपने विभागों के भीतर एआई पहलों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

Key Points:-

(i) प्रशिक्षण में AI नीति ढांचे, नैतिकता और कानूनी आयाम, डिजिटल परिवर्तन पद्धतियां और शासन में वास्तविक दुनिया के एआई अनुप्रयोगों को शामिल किया गया। इसमें विभागीय उपयोग के अनुरूप समूह अभ्यास और उपयोग-मामले विश्लेषण जैसे इंटरैक्टिव मॉड्यूल शामिल थे।

(ii) कुशल निर्णय लेने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए AI पर जोर देते हुए, कार्यक्रम अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा में उभरते उपकरणों को एकीकृत करने के लिए सक्षम बनाता है - जो भारत के प्रौद्योगिकी-संचालित, जवाबदेह शासन पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(iii) IIT दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग में आयोजित इस कार्यशाला में अकादमिक कठोरता को व्यावहारिक शासन आवश्यकताओं के साथ जोड़ा गया है। यह प्रासंगिक और उच्च प्रभाव वाले प्रशिक्षण वितरण के लिए प्रमुख संस्थानों तक NeGD की रणनीतिक पहुंच का उदाहरण है।

2. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचे और ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी।



25 जून 2025 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अलावा पुणे मेट्रो चरण II की मंजूरी, आगरा

में एक वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना और आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव सहित प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी गई।

- कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें दो एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं- वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2A) और रामवाड़ी से वाघोली-विठ्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2B)। 3,626 करोड़ रुपये की इस परियोजना से भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने और शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्वीकृत किया गया है। पाककला और कृषि अनुसंधान पर केंद्रित इस केंद्र का उद्देश्य वैश्विक आलू उत्पादन को बढ़ाना और कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों को विकसित करना है।

- 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, मंत्रिमंडल ने संवैधानिक स्वतंत्रता के निलंबन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

Key Points:-

(i) आपातकालीन प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, मंत्रियों ने उस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक लोकाचार की रक्षा करने वालों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।

(ii) प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आपातकाल किस तरह संघवाद, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर हमला था। इसमें नागरिकों-खासकर युवाओं से इस अवधि से सबक लेने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया गया।

(iii) मेट्रो और अनुसंधान केंद्र अनुदानों के साथ, कैबिनेट के 25 जून के सत्र ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि अनुसंधान और ऐतिहासिक-संवैधानिक प्रतिबिंब के बीच संतुलन प्रदर्शित किया, जिससे विरासत में निहित प्रगति के

दृष्टिकोण को बल मिला।

3. भारत ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहली AI-संचालित स्मार्ट ट्रेफिक प्रणाली शुरू की, जिससे राजमार्ग सुरक्षा बढ़ी।



25 जून 2025 को, भारत ने द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 के 56.46 किलोमीटर लंबे हिस्से पर अपना अग्रणी AI-संचालित उन्नत ट्रेफिक प्रबंधन सिस्टम (ATMS) पेश किया। NHA के तहत भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) द्वारा विकसित, यह भारत की बुद्धिमान, सुरक्षित राजमार्ग अवसंरचना में प्रगति को दर्शाता है।

- ATMs लगभग 56.46 किलोमीटर तक संचालित होता है, जिसमें NH-48 पर शिव मूर्ति से खेड़की दौला तक 28 किलोमीटर और द्वारका एक्सप्रेसवे पर 28.46 किलोमीटर शामिल है। यह इसे भारत में सबसे बड़ी AI-ट्रेफिक तैनाती के रूप में चिह्नित करता है।

- 14 यातायात उल्लंघनों का पता लगाने में सक्षम - जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, तीन लोगों के सवार होना, सीटबेल्ट और हेलमेट का उल्लंघन शामिल है - यह प्रणाली मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करती है और कानून प्रवर्तन में सहायता करती है।

- यह प्रणाली 1 किमी के अंतराल पर 110 उच्च-रिज़ॉल्यूशन PTZ कैमरे, वीडियो घटना पहचान और प्रवर्तन प्रणाली (VIDES), रडार इकाइयां, गति प्रदर्शन बोर्ड,

परिवर्तनीय संदेश साइनबोर्ड और एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर को एकीकृत करती है।

Key Points:-

(i) ATMs तत्काल जुर्माना लगाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई-चालान पोर्टल और स्थानीय पुलिस से जुड़ता है। नियंत्रण कक्ष अलर्ट भेजता है और घटनाओं की निगरानी करता है, जबकि जन जागरूकता अभियान तकनीकी प्रवर्तन का पूरक है।

(ii) दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों को कवर करते हुए, यह प्रणाली दुर्घटनाओं को कम करने, गलत रास्ते पर जाने से रोकने और आपात स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करती है - जिससे महत्वपूर्ण उपनगरीय गलियारे पर सुरक्षित, सुगम आवागमन संभव हो पाता है।

(iii) NHA के 2023 स्मार्ट हाईवे दिशानिर्देशों के अनुरूप एक पायलट के रूप में, यह ATMs भविष्य के गलियारों के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है - जो संभवतः पूरे भारत में UER-II और अन्य प्रमुख एक्सप्रेसवे तक विस्तारित होगा।

4. भारत सरकार ने EMC 2.0 योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर, यूपी में 417 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी।



25 जून, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को मजबूत करने, MSMEs और स्टार्ट-अप को

समर्थन देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 206 एकड़ में फैले 417 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) को मंजूरी दी।

• केंद्र सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा प्रबंधित गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 10 में 206.4 एकड़ से अधिक भूमि के विकास के लिए EMC2.0 योजना के तहत ₹417 करोड़ आवंटित किए। यह सरकार की “मेक इन इंडिया” और विकसित भारत रणनीतियों का हिस्सा है।

• इस क्लस्टर से 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निजी निवेश आकर्षित होने और लगभग 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करके इलेक्ट्रॉनिक्स-केंद्रित MSMEs और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा।

• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण उद्योगों को क्लस्टर में सेवाएं दी जाएंगी। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड को 50 एकड़ के समर्पित आवंटन के साथ एंकर किरायेदार के रूप में चुना गया है।

Key Points:-

(i) इस साइट में आवश्यक साझा सुविधाएं शामिल हैं: फैक्ट्री शेड, पानी और बिजली की व्यवस्था, सीवेज उपचार, कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास - जिससे छोटी फर्मों के लिए स्थापना संबंधी बाधाएं कम हो जाती हैं।

(ii) यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आगामी पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे के साथ-साथ और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट रणनीतिक रूप से स्थित यह स्थल बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और मेडिकल डिवाइस पार्क और MSME एवं अपैरल पार्क जैसे औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है।

(iii) यह क्लस्टर भारत के EMC परिदृश्य में इज़ाफा करता है, जिसने पहले ही 520 कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये

से अधिक के संचयी निवेश के साथ आकर्षित किया है, जिससे अब तक 86,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। यह भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनने, आयात निर्भरता को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पुष्ट करता है।

5. AMRUT मिशन ने जून 2015 में लॉन्च के बाद शहरी परिवर्तन के 10 वर्ष पूरे किए।



25 जून 2015 को शुरू किए गए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) ने भारतीय शहरों को बेहतर जल, स्वच्छता, गतिशीलता और हरित स्थानों के साथ बदलने के 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2.73 लाख करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है, जिससे लाखों शहरी निवासियों के जीवन में ठोस बदलाव आया है।

- एक दशक में AMRUT और AMRUT 2.0 के तहत कुल ₹2.73 लाख करोड़ की 14,828 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें से ₹1.12 लाख करोड़ का भौतिक कार्य पूरा हो चुका है, जिससे 485 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- इस अभियान के परिणामस्वरूप 2.03 करोड़ नए घरेलू नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन दिए गए, जिससे बुनियादी सुविधाएं अधिक सुलभ हो गईं और अमृत 2.0 शहरों में 67 लाख से अधिक परिवारों को भूमिगत जल निकासी में स्थानांतरित करने में मदद मिली।

- शहरी बाढ़ को कम करने के लिए AMRUT ने आधुनिक जल निकासी प्रणालियों का निर्माण किया। इसने चरण-1 में 1,700 से अधिक बाढ़-ग्रस्त स्थानों को समाप्त कर दिया, जबकि AMRUT 2.0 का लक्ष्य 500 शहरों में पूर्ण भूमिगत जल निकासी सुनिश्चित करना है, जिसे जियो-टैग्ड परियोजनाओं द्वारा समर्थित किया जाएगा।

Key Points:-

(i) नागरिकों को 9,500 एकड़ से अधिक पार्कों और 544 पुनर्जीवित जल निकायों तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे मनोरंजन, जैव विविधता और शहरी शीतलन को बढ़ावा मिला - जो टिकाऊ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ii) AMRUT 2.0 ने भू-टैग्ड जल कार्य योजनाएं, पेयजल सर्वेक्षण शहर रैंकिंग शुरू की, और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित किया - जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हुई।

(iii) प्रौद्योगिकी उप-मिशन के माध्यम से, AMRUT ने 82 शहरों में शहरी समाधान के लिए 120 स्टार्ट-अप को चुना। AMRUT मित्र पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की 10,000 से अधिक महिलाओं ने 1,762 शहरी परियोजनाओं में योगदान दिया, जिससे उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला।

INTERNATIONAL

1. UAE-भारत CEPA परिषद ने सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्ट-अप श्रृंखला' शुरू की।



24 जून 2025 को, UAE-भारत CEPA परिषद (UICC) ने भारत में UAE दूतावास के साथ साझेदारी में, नई दिल्ली में पहली बार "UAE-भारत CEPA स्टार्ट-अप सीरीज" शुरू की। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) द्वारा समर्थित, इस पहल का उद्देश्य UAE पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन के माध्यम से 5 चयनित भारतीय स्टार्ट-अप को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करना है।

- स्टार्ट-अप श्रृंखला CEPA का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसे नवाचार आधारित व्यापार को बढ़ावा देने तथा UAE के निवेशकों तक पहुंच, लाइसेंसिंग और पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन प्रदान करके भारतीय स्टार्ट-अप्स को अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत नवाचार सहयोग को मजबूती मिलेगी।

- प्रतिष्ठित ताज महल होटल में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व UAE के राजदूत डॉ अब्दुलनासर अलशाली ने किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "स्टार्ट-अप UAE-भारत आर्थिक गलियारे के लिए केंद्रीय हैं", जो उद्यमशीलता पर UAE के रणनीतिक फोकस को मजबूत करता है।

- कार्यक्रम का समापन नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय पिच इवेंट में होगा, जहां पांच भारतीय स्टार्ट-अप को UAE सॉफ्ट-लैंडिंग पैकेज प्राप्त होंगे - जिसमें इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, लाइसेंसिंग और UAE फ्री-ज़ोन निवेशकों तक पहुंच शामिल है।

Key Points:-

(i) राज्यों में क्षेत्रीय नवाचार आदान-प्रदान, अनुसंधान साझेदारी और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए प्राइम मेघालय, ओ.पी. ज़िंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में IDEATE लैब और जामिया हमदर्द जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) भारत-UAE व्यापार में वृद्धि हुई है - वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापार 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, गैर-तेल निर्यात 20% बढ़ा और भारत में UAE का FDI तीन गुना बढ़कर 3.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे यह भारत का चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया।

(iii) CEPA स्टार्ट-अप सीरीज माइक्रोसाइट के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन खुले हैं। लॉन्च में 100 से अधिक निवेशक, कॉरपोरेट और इकोसिस्टम प्लेयर्स शामिल हुए, जो मजबूत क्रॉस-बॉर्डर जुड़ाव का संकेत है।

2. बोत्सवाना HIV संक्रमण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया।



मई 2025 में, बोत्सवाना विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गोल्ड टियर प्रमाणीकरण के साथ HIV के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश और दुनिया में सबसे अधिक HIV -ग्रस्त

देशों में से एक बनकर एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मील का पत्थर हासिल करेगा।

- यह मान्यता WHO की ट्रिपल एलिमिनेशन पहल के तहत दी गई है, जिसे UNAIDS (HIV/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम), UNICEF (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। यह HIV, सिफलिस और हेपेटाइटिस बी संक्रमण को खत्म करने के लिए एकीकृत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है।

- बोत्सवाना इससे पहले 2021 में WHO के सिल्वर टियर प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऊर्ध्वाधर HIV संचरण को कम करने में इसकी लगातार प्रगति ने अब इसे वैश्विक HIV नियंत्रण की शीर्ष श्रेणी में रखा है।

Key Points:-

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बोत्सवाना ने गोल्ड टियर दर्जे के लिए आवश्यक सभी कठोर मानदंडों को पूरा कर लिया है - जैसे कि प्रति 100,000 जीवित जन्मों में नए बाल चिकित्सा HIV संक्रमण को 50 से कम करना, तथा HIV पॉजिटिव माताओं में समग्र HIV संचरण दर को 5% से कम करना।

(ii) UNAIDS स्पेक्ट्रम रिपोर्ट 2024 के अनुसार, बोत्सवाना में लगभग 360,000 लोग HIV से पीड़ित हैं। हालाँकि, देश में HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं में से लगभग 98% को अब प्रभावी एंटीरेट्रोवायरल उपचार मिल रहा है, जिससे बच्चों में संक्रमण की दर घटकर सिर्फ 1.2% रह गई है और 2023 में 100 से कम बच्चे HIV से पीड़ित पैदा होंगे।

(iii) वैश्विक स्तर पर, क्यूबा 2015 में WHO के HIV और सिफलिस उन्मूलन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश था। 2025 तक, 16 देशों और क्षेत्रों को HIV के माँ से बच्चे में संचरण को खत्म करने के लिए प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिनमें से 11 कैरिबियन क्षेत्र में हैं।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने बताया कि "भारत 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीनफील्ड निवेश के लिए ग्लोबल साउथ में शीर्ष स्थान पर है"।



जून 2025 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत ने ग्रीनफील्ड निवेश में रिकॉर्ड 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किए हैं - जिससे यह ग्लोबल साउथ में नंबर एक गंतव्य बन गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती अपील को दर्शाता है।

- ग्रीनफील्ड निवेश में मेजबान देश में नई सुविधाएं या संपत्तियां स्थापित करना शामिल है। RBI की जून 2025 की "विदेशी निवेश पर डेटा" रिपोर्ट में भारत के 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीनफील्ड प्रवाह पर प्रकाश डाला गया है - जो अन्य सभी वैश्विक दक्षिण अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है।

- पिछले वर्षों में दूसरे स्थान से आगे बढ़ते हुए, भारत अब वैश्विक दक्षिण में ग्रीनफील्ड निवेश प्राप्तकर्ताओं की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है।

- इस वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डेटा सेंटर, डिजिटल बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं - जो भारत की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप हैं।

Key Points:-

(i) जबकि FDI इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 25 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया - जिससे भारत को UNCTAD के अनुसार 15वीं वैश्विक रैंक प्राप्त हुई - ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का परिमाण पूंजी-गहन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में व्यापक रुचि को दर्शाता है।

(ii) ये निवेश औद्योगिक क्षमता में वृद्धि, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात में वृद्धि और आयात पर निर्भरता को कम करने में योगदान देते हैं - जो भारत के विनिर्माण-आधारित विकास मॉडल में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।

(iii) इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, भारत व्यापार को आसान बनाने, अपने लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) की पेशकश करने और यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्मार्ट, लचीली बचत के लिए 'बॉब फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान' पेश किया।



25 जून 2025 को, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 'बॉब फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान (SDP)' शुरू की, जो एक आधुनिक आवर्ती-जमा योजना है, जो केवल ₹500 से शुरू होने वाले मासिक निवेश की अनुमति देती है - ₹1 लाख तक

लचीली - और पूरे कार्यकाल के लिए प्रत्येक योगदान पर निश्चित ब्याज दरों को लॉक करती है।

- ग्राहक 500 रुपये की मूल किस्त से शुरुआत कर सकते हैं और बाद में मासिक जमा राशि को 10x (100 रुपये के गुणकों में) तक बढ़ा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह है - जो उन लोगों के लिए आदर्श है जिनकी आय या बोनस प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

- प्रत्येक मासिक योगदान पूरी जमा अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर में लॉक हो जाता है, चाहे वह कब भी किया गया हो। उदाहरण: 2-वर्षीय योजना नियमित ग्राहकों के लिए 6.50% प्रति वर्ष, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.00% और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.10% प्रदान करती है।

- यह योजना अनुशासित बचत को लचीलेपन के साथ मिश्रित करती है तथा बिना किसी बाजार जोखिम के सामान्य सावधि जमा खातों की तुलना में अधिक रिटर्न का आश्वासन देती है - जिससे यह शिक्षा, यात्रा या आपातकालीन निधि जैसे लक्ष्यों के लिए एकदम उपयुक्त बन जाती है।

Key Points:-

(i) ग्राहक संचित शेष राशि के 95% तक ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे बचत करते समय भी वित्तीय लचीलापन मिलता है। इसके अतिरिक्त, नामांकन सुविधा भी उपलब्ध है।

(ii) सभी निवासी व्यक्तियों के लिए खुला है - जिसमें नाबालिग (10 वर्ष से अधिक) और वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं - जिसकी कुल जमा सीमा ₹3 करोड़ है। इस योजना में नामांकन, लचीली अवधि (6 महीने से 5 वर्ष) और कोई बाजार जोखिम शामिल नहीं है।

ECONOMY & BUSINESS

1. टाटा 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है और 30

बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया ।



25 जून 2025 को, ब्रांड फाइनेंस ने अपनी इंडिया100 2025 रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत के शीर्ष 100 ब्रांडों के लिए कुल संयुक्त मूल्य 236.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया। टाटा समूह ने 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा - 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मील का पत्थर पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड।

- टाटा समूह का ब्रांड मूल्य 10% बढ़कर 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे यह शीर्ष रैंक हासिल करने के साथ ही 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया - इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, सेमीकंडक्टर, AI और नवीकरणीय ऊर्जा में विविधीकरण के कारण।

- इंफोसिस (IT) 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (+15%) तक पहुंच गया, HDFC ग्रुप (बैंकिंग) 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (+37%) तक पहुंच गया, और LIC (बीमा) 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (+35%) तक पहुंच गया - ये सभी शीर्ष पांच भारतीय ब्रांडों में मजबूत स्थिति में हैं।

- अडानी समूह ने वर्ष-दर-वर्ष ब्रांड-मूल्य में 82% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, जो बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और हितधारकों के विश्वास में वृद्धि में इसके आक्रामक विस्तार से प्रेरित है।

Key Points:-

(i) ताज होटल्स ने 92.2 के AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) स्कोर के साथ भारत के सबसे मजबूत ब्रांड का खिताब बरकरार रखा, जिसके बाद एशियन पेंट्स (92.0) और अमूल (91.2) का स्थान रहा, जिसने ब्रांड उत्कृष्टता में निरंतर नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

(ii) भारत की शीर्ष 100 कंपनियों का संचयी ब्रांड मूल्य 236.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो प्रौद्योगिकी, वित्त, बुनियादी ढांचे, आतिथ्य और विशिष्ट विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापक लाभ का संकेत है।

(iii) वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP 6%-7% के बीच बढ़ने की उम्मीद है, मजबूत घरेलू मांग, बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय और मजबूत सार्वजनिक-निजी सहयोग ब्रांड मूल्य और विदेशी प्रभाव को बढ़ा रहे हैं।

MOUs and Agreement

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय और MSDE ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल, उद्यमिता और बाजार पहुंच के साथ सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



25 जून 2025 को, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नई दिल्ली के कृषि भवन में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य DAY-NRLM और

लखपति दीदी मिशन के तहत ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कौशल प्रदान करना, सशक्त बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

- ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कौशल राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस समझौता ज्ञापन का समर्थन किया, जो विकसित भारत@2047 और लखपति दीदी के लक्ष्यों से जुड़ा है। इस साझेदारी का उद्देश्य लक्षित प्रशिक्षण और उद्यमशीलता सहायता के माध्यम से ग्रामीण भारत में तीन करोड़ स्वयं सहायता समूह महिलाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है।

- MoU में उभरते क्षेत्रों- डिजिटल, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन और बाजार पहुंच में SHGs महिलाओं के लिए अनुकूलित कौशल मॉड्यूल अनिवार्य किए गए हैं। जन शिक्षण संस्थान, RSETIs, NIESBUD और NSTIs जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें स्किल इंडिया डिजिटल हब द्वारा समर्थित प्रमाणन होगा।

- व्यवहार्य ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई यह पहल कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में SHGs का समर्थन करती है। संयुक्त आजीविका मेले, जागरूकता अभियान, मेंटरशिप कार्यक्रम और संयुक्त समिति द्वारा तिमाही समीक्षा इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हैं।

Key Points:-

(i) यह समझौता ज्ञापन संस्थागत अभिसरण बनाता है - ग्रामीण विकास मंत्रालय का DAY-NRLM जमीनी स्तर का नेटवर्क और MSDE का क्षमता विकास पारिस्थितिकी तंत्र - दोनों मंत्रालयों को एक समन्वित कौशल-उद्यमिता वितरण मॉडल में लाता है। यह एक सुसंगत "अंतिम-मील" सशक्तिकरण प्रणाली स्थापित करता है।

(ii) तीन वर्षों के लिए वैध, यह समझौता ज्ञापन तिमाही निगरानी के लिए एक संयुक्त समीक्षा समिति की स्थापना करता है। ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह और MSDE सचिव अतुल कुमार तिवारी, अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे, जिससे समय पर प्रगति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

(iii) DAY-NRLM के तहत 91 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को पहले ही संगठित किया जा चुका है, मंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं बदलाव की अगुआई कर रही हैं। यह क्षमता निर्माण सामाजिक-आर्थिक प्रतिमानों को बदलने और भविष्य के चरणों में 'करोड़पति दीदी' जैसे लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक है।

SPORTS

1. ICC ने WTC 2025-27 के लिए 'स्टॉप-क्लॉक' और नई खेल स्थितियां पेश कीं।



अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2025-27 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र के लिए खेल की स्थिति में बड़े बदलाव किए हैं - जिसमें टेस्ट मैचों में पहली बार स्टॉप-क्लॉक और खेल को गति देने और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए नए सामरिक नियम शामिल हैं।

- ICC अब फील्डिंग करने वाली टीमों को पिछले ओवर के खत्म होने के 60 सेकंड के भीतर प्रत्येक ओवर शुरू करने की आवश्यकता रखता है। उल्लंघन के लिए दो चेतावनी मिलती है; तीसरे उल्लंघन के परिणामस्वरूप बल्लेबाजी करने वाली टीम को पांच रन की पेनल्टी दी जाती है। हर 80 ओवर के बाद घड़ी रीसेट हो जाती है।

- स्टॉप-क्लॉक नियम सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट के 'पावरप्ले' सिस्टम की तरह है और इसका उद्देश्य टेस्ट में धीमी गति

वाले ओवरों पर लगाम लगाना है - एक ऐसी समस्या जो मैच के प्रवाह को बाधित करती है। गॉल में श्रीलंका बनाम बांग्लादेश सीरीज़ के बाद से यह WTC मैचों में पहले से ही सक्रिय है।

Key Points:-

(i) जानबूझकर कम रन बनाने के मामले में, क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम अब यह चुन सकती है कि अगला बल्लेबाज कौन सा स्ट्राइक लेगा - इससे सामरिक गहराई बढ़ेगी और अनुचित बल्लेबाजी रणनीति को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

(ii) ICC ने DRS प्रोटोकॉल में भी सुधार किया है: यदि अंपायर के आउट के निर्णय को ट्रैकर द्वारा "अंपायर की कॉल" के रूप में बरकरार रखा जाता है, तो अब निर्णय आउट ही रहेगा। इसके अतिरिक्त, अंपायरों को अब सिर्फ इसलिए गेंद बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लार का इस्तेमाल किया गया था - हालाँकि लार पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

(iii) अपडेट किए गए नियमों के अनुसार अब थर्ड अंपायर नो-बॉल पर लिए गए कैच को सत्यापित कर सकता है। अगर यह उचित पाया जाता है, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक रन मिलता है; अगर ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें कैच से पहले रन पूरे करने का मौका मिलता है - जिससे विवादास्पद निर्णय कम हो जाते हैं।



26 जून 2025 को विश्व प्रशीतन दिवस आधुनिक जीवन में प्रशीतन, एयर-कंडीशनिंग, हीट पंप और संधारणीय हीटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम, "कूल स्किल्स" के साथ, यह दिन स्वास्थ्य, सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन के लिए आवश्यक तापमान-नियंत्रित प्रणालियों के पीछे पेशेवर विशेषज्ञता का जश्न मनाता है।

● 26 जून 2019 से हर साल मनाया जाने वाला विश्व प्रशीतन दिवस थर्मोडायनामिक्स के अग्रणी लॉर्ड केल्विन (जन्म 1824) की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे सलाहकार स्टीफन गिल द्वारा शुरू किया गया था और इसे ASHRAE और UNEP से शुरुआती समर्थन मिला था।

● इस वर्ष का फोकस तकनीशियनों से लेकर शोधकर्ताओं तक की आवश्यक योग्यताओं का जश्न मनाता है, जो आधुनिक रेफ्रिजरेशन, एयर-कंडीशनिंग, हीट पंप और संधारणीय हीटिंग सिस्टम को सक्षम बनाती हैं। यह ऊर्जा-कुशल और कम कार्बन वाले कूलिंग समाधानों में कुशल पेशेवरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

● शीतलन तकनीकें वैक्सीन की अखंडता सुनिश्चित करती हैं, ताजा भोजन को संरक्षित करने में सक्षम बनाती हैं, डेटा केंद्रों का समर्थन करती हैं, और आरामदायक इनडोर वातावरण प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन में प्रशीतन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

Key Points:-

IMPORTANT DAYS

1. विश्व प्रशीतन दिवस 2025: शीतल कौशल का जश्न मनाने के लिए 26 जून को मनाया गया।

(i) रेफ्रिजरेशन सिस्टम वैश्विक भवन ऊर्जा उपयोग का लगभग 20% हिस्सा है। ऊर्जा दक्षता में सुधार, कम कार्बन वाले रेफ्रिजरेट को अपनाना और प्रशिक्षित पेशेवरों को नियुक्त करना जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण कदम हैं।

(ii) ASHRAE UNEP के ओजोन एक्शन कार्यक्रम के सहयोग से शिक्षा, प्रमाणन और स्थिरता चेकलिस्ट के माध्यम से “कूल स्किल्स” को बढ़ावा देता है। IIR (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन) ने पेरिस में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, इंजीनियर और वैज्ञानिक एक साथ आए।

(iii) चूंकि खाद्य संरक्षण आवश्यकताओं, जलवायु लचीलेपन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण कोल्ड चेन सेवाओं और टिकाऊ शीतलन की मांग बढ़ रही है, इसलिए विश्व प्रशीतन दिवस 2025 का उद्देश्य जागरूकता अभियानों, कैरियर ड्राइव, वेबिनार और तकनीकी प्रदर्शनों के माध्यम से एचवीएसी और आर पेशेवरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना है।

2. भारत ने विकास को गति देने वाले छोटे व्यवसायों को सम्मानित करने के लिए 27 जून को MSME दिवस 2025 मनाया।



भारत ने 27 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (MSME) दिवस मनाया, जिसमें नवाचार,

रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यह दिन 2017 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।

● यह दिन MSME दिवस के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जिसे अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा संकल्प A/RES/71/279 के माध्यम से घोषित किया गया था। सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में छोटे व्यवसायों के महत्व को पहचानने के लिए इसे 2018 से हर साल मनाया जाता है।

● भारत का MSME क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक, निर्यात में 45% का योगदान देता है और 6.3 करोड़ इकाइयों के माध्यम से 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन का एक प्रमुख स्तंभ है।

Key Points:-

(i) 2025 में, थीम थी “स्थायी विकास और नवाचार के चालकों के रूप में MSMEs की भूमिका को बढ़ाना।” MSME मंत्रालय ने पूरे भारत में जागरूकता अभियान, प्रदर्शनियाँ और कौशल प्रशिक्षण पहल सहित कार्यक्रम आयोजित किए।

(ii) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय MSME सम्मेलन को संबोधित किया और छोटे व्यवसायों द्वारा सामना किए जाने वाले वाणिज्यिक विवादों को अधिक कुशलता से हल करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल लॉन्च किया।

(iii) मजबूत योगदान के बावजूद, इस क्षेत्र को औपचारिक ऋण तक पहुँच, डिजिटल अपनाने और बाजार से जुड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने लक्षित नीति सुधारों के माध्यम से MSMEs के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

3. 26 जून 2025 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।



26 जून 2025 को, विश्व नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया - जिसे विश्व नशीली दवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है - ताकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसे बढ़ावा देने वाले संगठित अपराध के व्यापक प्रभाव से निपटने में वैश्विक कार्रवाई और सहयोग को मजबूत किया जा सके।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में प्रस्ताव 42/112 के तहत आधिकारिक तौर पर 26 जून को दिवस के रूप में नामित किया। यह 1839 में अफीम व्यापार के खिलाफ चीन की निर्णायक कार्रवाई की याद दिलाता है और इसका उद्देश्य नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों और बहुपक्षीय सहयोग को संगठित करना है।

- 2025 का थीम - "चक्र को तोड़ो। #संगठित अपराध को रोकें" - नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के बीच अटूट संबंध को उजागर करता है। यह रोकथाम, उपचार, पुनर्प्राप्ति और प्रवर्तन में निरंतर हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार, 2022 में 15-64 वर्ष की आयु के लगभग 292 मिलियन व्यक्तियों ने अवैध ड्रग्स का उपयोग किया - जो

पिछले दशक की तुलना में 20% की वृद्धि है। यह वृद्धि मांग को बढ़ाती है, आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक तनाव को बढ़ाती है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठित ड्रग अपराध के खिलाफ रोकथाम को "सबसे आवश्यक रणनीति" बताया। उन्होंने न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नुकसान में कमी और व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका में संतुलित निवेश का आह्वान किया।

(iii) दिल्ली, नागालैंड, कोच्चि, बेलगावी और पटना समेत पूरे भारत में स्थानीय अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने जागरूकता रैलियां, स्कूल कार्यक्रम और सार्वजनिक शपथ ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया - 2025 की शुरुआत में की गई 1,100 से अधिक गिरफ्तारियों पर प्रकाश डाला - और 2047 तक नशा मुक्त होने के भारत के दृष्टिकोण को दोहराया।

4. संयुक्त राष्ट्र ने 26 जून 2025 को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।



संयुक्त राष्ट्र ने यातना के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के लिए न्याय, पुनर्वास और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए 26 जून, 2025 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।

● यह दिन यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 26 जून 1987 को लागू हुआ था। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यातना के पूर्ण निषेध को बढ़ावा देता है।

● संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को प्रस्ताव 52/149 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की। यह यातना के पीड़ितों के लिए समर्थन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से उनके कानूनी और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने का काम करता है।

Key Points:-

(i) 2025 में, वैश्विक विषय "यातना: मानवता के खिलाफ अपराध" पर केंद्रित है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी परिस्थितियों में यातना सख्त वर्जित है और इसे केवल घरेलू मामला नहीं बल्कि एक दंडनीय अंतरराष्ट्रीय अपराध माना जाना चाहिए।

(ii) इस दिन को यातना पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कोष द्वारा समर्थित किया जाता है, जो पीड़ितों को मानवीय, चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल से हर साल 80 से ज़्यादा देशों में 600 से ज़्यादा संगठन लाभान्वित होते हैं।

(iii) 26 जून का दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के कारण भी महत्वपूर्ण है, जो मानव सम्मान, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

DEFENCE

1. रिलायंस डिफेंस को जर्मनी की राइनमेटल से 600 करोड़ रुपये का गोला-बारूद निर्यात ऑर्डर मिला।



25 जून 2025 को, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक सहायक कंपनी) ने जर्मनी स्थित राइनमेटल वेफ म्यूनिशन GmbH के साथ 600 करोड़ रुपये का एक प्रमुख निर्यात अनुबंध हासिल किया - यह एक मील का पत्थर सौदा है जो निजी क्षेत्र के रक्षा निर्यात में भारत के उदय का संकेत देता है।

● 600 करोड़ रुपये का यह ऑर्डर उच्च तकनीक वाले गोला-बारूद श्रेणी में किसी भारतीय निजी रक्षा फर्म द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा है, जो राइनमेटल के साथ हाल ही में शुरू की गई रणनीतिक साझेदारी के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

● रिलायंस डिफेंस महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी (DADC) परियोजना के तहत एक नई ग्रीनफील्ड सुविधा के माध्यम से मध्यम से बड़े कैलिबर के गोला-बारूद - जैसे तोपखाने के गोले, विस्फोटक और प्रणोदक - का निर्माण और आपूर्ति करेगी।

● वटद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी संयंत्र दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला-बारूद संयंत्रों में से एक होगा - जिसमें प्रतिवर्ष 2 लाख तोप के गोले, 10,000 टन विस्फोटक और 2,000 टन प्रणोदक का उत्पादन होगा।

Key Points:-

(i) घोषणा के जवाब में, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लगभग 5% की वृद्धि हुई - जो सकारात्मक बाजार भावना और भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं की अंतर्राष्ट्रीय

मान्यता को दर्शाता है।

(ii) यह निर्यात सौदा प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण के दृष्टिकोण को बल देता है, भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला उपस्थिति को मजबूत करता है और एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में इसकी स्थिति को आगे बढ़ाता है।

(iii) यह प्रमुख अनुबंध जून 2025 में जर्मनी की डाइहल डिफेंस के साथ इसी तरह के ₹10,000 करोड़ के गोला-बारूद समझौते के तुरंत बाद आया है। ये समझौते भारत को 2029 तक अपने ₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब लाते हैं।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. शुभांशु शुक्ला Axiom-4 मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बने।



25-26 जून 2025 को, भारतीय वायु सेना के परीक्षण पायलट और इसरो अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने स्पेसएक्स के क्यू ड्रैगन पर सवार होकर एक्सिओम-4 को लॉन्च किया। वे अंतरिक्ष में जाने वाले 634वें इंसान और चार दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर डॉक करने वाले पहले भारतीय बन गए।

● शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और आई.एस.एस. पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे भारत के लिए गौरव की बात है,

क्योंकि उन्होंने देश की मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ा है।

● डॉकिंग के दौरान Axiom-4 कमांडर पैगी व्हिटसन ने कैप्टन शुक्ला को आधिकारिक तौर पर 634वें अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया। वे दो सप्ताह के आईएसएस प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन के लिए मिशन पायलट की भूमिका निभाएंगे।

● क्यू ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस 26 जून को ISS से जुड़ गया। 4-व्यक्ति Axiom-4 चालक दल का स्वागत एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों ने किया, और शुक्ला ने 14-दिवसीय प्रवास के दौरान माइक्रोग्रैविटी प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

Key Points:-

(i) इसरो ह्यूस्टन से शुक्ला के मिशन की निगरानी कर रहा है, जिससे 2027 के लिए नियोजित अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रशिक्षण, डॉकिंग और अनुसंधान डेटा भारत के स्वायत्त चालक दल मिशनों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

(ii) 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISS पर मौजूद शुक्ला को फोन किया। इस कॉल में खुशनुमा बातें शामिल थीं - यहां तक कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में "गाजर का हलवा" तैरने के बारे में भी - और राकेश शर्मा के प्रतिष्ठित प्रसारण की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं।

(iii) CM योगी आदित्यनाथ की बधाई से लेकर भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन में फिर से प्रवेश करने पर वैश्विक उत्साह तक, जनता की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। शुक्ला के गृहनगर लखनऊ और इसरो अधिकारियों ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया।

Static GK

National e-Governance Division (NeGD)	CEO : नंदकुमारम	मुख्यालय: नई दिल्ली
MSDE	मंत्री: जयंत चौधरी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
UAE	राजधानी: अबू धाबी	राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Bank of Baroda	CEO : श्री देबदत्त चंद	मुख्यालय: अलकापुरी, वडोदरा
Tata Group	अध्यक्ष: नटराजन चन्द्रशेखरन	मुख्यालय: मुंबई
Botswana	राष्ट्रपति: मोकवेत्सी मसीसी	राजधानी: गैबोरोन